

**केशो राम खुशी राम बनाम आयकर आयुक्त, हरियाणा  
(जी.सी.मितल, जे.)**

जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस आशय के सकारात्मक निर्देश हैं "जैसे कि जब कोई अधिकारी इक्कीस दिनों के लिए किसी विशेष नियुक्ति में अनुशासनात्मक आधार पर संलग्न होने के कारण या अस्पताल में भर्ती होने के कारण बीमारी के कारण अप्रभावी हो जाता है, तो वह कार्यवाहक पद छोड़ देता है।" वह अब उन कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें अभिनय पद दिया गया था।" अधिकारियों की कार्रवाई इन निर्देशों के अनुसार सख्ती से की गई है और इसलिए, इसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

(11) उपरोक्त कारणों से, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया जाता है, अपील की अनुमति दी जाती है और रिट याचिका खारिज कर दी जाती है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

**आर.एन.आर.**

**पहले: जी. सी. मितल और एस. एस. सोढ़ी, जे.जे.**

**केशो राम खुशी राम,—निवेदक**

**बनाम**

**आयकर आयुक्त, हरियाणा, - प्रतिवादी।**

**1982 का आयकर संदर्भ संख्या 23**

**6 अप्रैल, 1989.**

आयकर अधिनियम (1961 का XLIII) धारा 271(एल)(सी) - निर्धारिती ने निर्धारित आय का 80 प्रतिशत से अधिक रिटर्न दिया - जुर्माना लगाने के लिए विभाग पर सबूत का बोझ - विभाग निर्धारिती पर बोझ डाल रहा है - कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया निर्धारिती द्वारा—विभाग द्वारा निर्धारिती पर जुर्माना लगाना—ऐसा लगाना—चाहे कानूनी हो।

माना गया कि हमारा विचार है कि ट्रिब्यूनल निर्धारिती पर सबूत का गलत बोझ डालकर जुर्माना बरकरार रखने में सही नहीं था। तदनुसार, निर्धारिती की अपील को नए सिरे से सुनने और कानून के अनुसार विभाग पर बोझ डालने के बाद नए निर्णय लेने के लिए मामला ट्रिब्यूनल को वापस भेजा जाता है।

(पैरा 3).

आयकर अधिनियम की धारा 271(एल)(सी) के तहत संदर्भ। 1961 आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ द्वारा, आईटीए में 13 मई, 1981 के न्यायाधिकरण के आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के निम्नलिखित प्रश्नों पर राय के लिए माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को। 1979 की संख्या 895, निर्धारण वर्ष 1974-75 :

“क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल ने रुपये का जुर्माना कायम रखने में कानूनी गलती की है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(एल)(सी) के तहत आयकर अधिकारी द्वारा लगाया गया 9400?”

### **आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा**

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बी.एस. गुप्ता और अधिवक्ता संजय बंसल।  
प्रतिवादी की ओर से अशोक भान, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजय मित्तल, अधिवक्ता।

### **फैसला**

*गोकल चंद मित्तल, जे.*

मूल्यांकन कार्यवाही में करदाता का अंतिम मूल्यांकन रु. रुपये की लौटाई गई आय के मुकाबले 50,892 रुपये। निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए 41,490। लौटाई गई आय मूल्यांकन की गई आय का 80 प्रतिशत से अधिक थी, और इसलिए, स्पष्टीकरण लागू नहीं था और यह दिखाने के लिए सबूत का बोझ विभाग पर था कि जुर्माना लगाया जा सकता था। हालाँकि, ऐसा लगता है कि ट्रिब्यूनल तक के सभी अधिकारियों ने निर्धारिती पर बोझ डाल दिया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि चूंकि निर्धारिती द्वारा कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए रुपये की छुपाई गई आय पर जुर्माना लगाया गया है। 9,400. तथ्यों पर ट्रिब्यूनल ने निर्धारिती के कहने पर राय के लिए निम्नलिखित प्रश्न भेजा है:

“क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल ने रुपये का जुर्माना कायम रखने में कानूनी गलती की है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1) (सी) के तहत आयकर अधिकारी द्वारा लगाया गया 9,400?”

यह विवाद से परे है कि स्पष्टीकरण लागू नहीं है क्योंकि लौटाई गई आय मूल्यांकन की गई आय का 80 प्रतिशत से अधिक थी और इस प्रकार, सबूत का बोझ विभाग पर था, लेकिन इस मामले में ट्रिब्यूनल के आदेश को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सबूत का भार निर्धारिती पर था और चूंकि वह कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहा, इसलिए जुर्माना लगाया

गया। चूंकि ट्रिब्यूनल ने मामले पर गलत दृष्टिकोण से विचार किया, इसलिए यह एक ऐसा मामला है जिसे कानून के अनुसार नए फैसले के लिए वापस भेजा जाना चाहिए।  
ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, हमारा विचार है कि करदाता पर सबूत का गलत बोझ डालकर जुर्माना बरकरार रखने में ट्रिब्यूनल सही नहीं था। तदनुसार, निर्धारिती की अपील को नए सिरे से सुनने और विभाग पर कानून के अनुसार बोझ डालने के बाद नया निर्णय लेने के लिए मामला ट्रिब्यूनल को वापस भेजा जाता है। संदर्भ का उत्तर पूर्वोक्त शर्तों में निर्धारिती के पक्ष में दिया गया है और पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

**अस्वीकरण:** स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

दीपाली सिंगला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा